भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1486
दिनांक 13 फरवरी, 2025

इथेनॉल मिश्रित ईंधन

1486. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की यह मानते हुए कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन हमारे देश के लिए पर्यावरणिक और आर्थिक रूप से बेहतर है, अधिक से अधिक इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने की योजना है और यदि हां, तो इसके वैज्ञानिक आंकड़ों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि इथेनॉल उत्पादन की प्रक्रिया काफी प्रदूषणकारी है और इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना उगाने से सीमित कृषि भूमि बर्बाद होती है तथा अति सीमित पानी भी कम हो जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): वर्ष 2022 में यथा संशोधित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 में अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोल में 20 % एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की समय-सीमा को वर्ष 2030 से घटाकर एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 कर दिया गया है साथ ही पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को अपनाने में तेजी लाई गई है। "भारत में एथेनॉल के मिश्रण के लिए रोड मैप 2020-25" में अनुमान लगाया गया है कि एक सफल ई20 (पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण) कार्यक्रम देश में प्रति वर्ष 4 बिलियन अमरीकी डॉलर (यूएसडी) को बचा सकता है। रोड मैप ने ई0 (शुद्ध पेट्रोल) की तुलना में ई20 का प्रयोग करते हुए चार पहिया वाहनों से 30% तथा दो पहिया वाहनों से लगभग 50% कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी होने का भी अनुमान लगाया था। दो पहिया वाहनों तथा यात्री कारों दोनों से ही 20% तक हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन की कमी होने का भी अनुमान लगाया गया है।

(ख): राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, भुट्टा, कसावा, सड़े आलू, टूटे चावल जैसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न, मक्का, गन्ने का रस और शीरा, कृषि अवशेष (चावल का भूसा, कपास डंठल, मकई का भुट्टा, लकड़ी का बुरादा खोई आदि) जैसे फीडस्टॉक के उपयोग को बढ़ावा देती तथा प्रोत्साहित करती है। वर्ष भर में एथेनॉल उत्पादन के लिए व्यक्तिगत फीडस्टॉक के उपयोग की सीमा उपलब्धता, लागत, आर्थिक व्यवहार्यता, बाजार की मांग और नीति प्रोत्साहन जैसे कारकों से प्रभावित होकर बदलती रहती है। सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए किसानों को चावल, गन्ना आदि जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों के स्थान पर मक्का जैसी अधिक संधारणीय फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। "भारत में एथेनॉल के मिश्रण के लिए रोड मैप 2020-25" में यह भी नोट किया गया है कि प्रौद्योगिकीय प्रगति से भस्मीकरण बॉयलरों तथा खाद्यान्न आधारित डिस्टलरियों के साथ शीरा-आधारित डिस्टलरियों को शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) इकाइयां बनाना संभव हो पाया है जिसके परिणामस्वरूप नगण्य प्रदूषण होता है।

****